खण्डः 2, अंकः 2 फरवरी 2019

संश्लेषण

डी सी आर सी हिन्दी मासिक पत्रिका

आतंकवाद

डी.सी.आर.सी.
विकासशील राज्य शोध केन्द्र
दिल्ली विश्वविद्यालय

मुख्य संपादक
प्रो. सुनील के चौधरी

संपादक
डा. रमेश भारद्वाज
नागेन्द्र कुमार
शरद कुमार यादव

संपादकीय मंडल
डा. अभिषेक नाथ
कुँवर प्रांजल सिंह
आशीष कुमार शुक्ल

© डीसीआरसी 2018

रूपाकंनः आर किशोर

संश्लेषण

मुख्य कथ्यः आतंकवाद

अनुक्रमिका i

संपादकीय ii

1.	आतंकवादः संक्षिप्त परिचय	– निशा कुमारी	1–2
2.	आतंकवादः विश्व जगत की विकराल समस्या	– शिम्पी पांडे	3–5
3.	आतंकवादः कारण एवं समाधान	– दिव्या राणा	6–8
4.	धर्म एवं आतंकवादः इस्लामिक आतंकवाद के संदर्भ में	– राहुल शर्मा	9–11
5.	भारत के लिए बाहरी आतंकवाद प्रमुख चुनौतीः सॉफट पॉवर द्वारा समाधान	– रोहित कुमार	12–13
6.	आतंकवादः राष्टीय सुरक्षा के विषय के रूप में	– सृष्टि	14–16
7.	ड्रग तस्करी व नार्को–आतंकवाद	– विजय प्रकाश सिंह	17–18
8.	विश्व एवं आतंकवाद	– मोहिनी	19–20
9.	आतंकवादः बदलता स्वरूप एवं चुनौतियॉ	– विद्यासागर शर्मा	21–22

संपादकीय

विकासशील राज्य शोध केन्द्र, दिल्ली विश्वविद्यालय की हिन्दी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के सप्तम अंक को प्रकाशित करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों द्वारा समसामयिक विषय पर अपने सामूहिक लेखों द्वारा शोध वास्तविकताओं के प्रकटीकरण के माध्यम से हिन्दी भाषा को प्रचारित, प्रसारित एवं प्रमाणित करने की हमारी यह पहल संश्लेषण के रूप में प्रस्तुत हो रही है। वर्ष 2019 का संश्लेषण का यह द्वितीय अंक सभी पाठकों को प्रेषित किया जा रहा है।

वर्ष 2019 का फरवरी माह भारत में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सीमा पर आतंकवाद ने पिछले कुछ माह में भारतीय सुरक्षा व भारतीय राज्य के समक्ष व्यापक चेतावनी प्रस्तुत की है। केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय गठबंधन सरकार के 2014 के आने के पश्चात आंतकवाद एवं सीमापार आंतकियों ने, विशेषकर जम्मू व कश्मीर में, आंतकी परिदृश्य को पुनः सुदृढ़ करने करने का प्रयास किया है। पाकिस्तान द्वारा छदम युद्ध के माध्यम से आंतकवाद की गतिविधियों का भारत में सवंर्द्धन निरंतर बढता रहा है। गत माह में उरी एवं पुलवामा में आंतकी घटनाओं ने भारतीय राज्य, शासन एवं सुरक्षा बलों के समक्ष कड़ी चुनौती प्रस्तुत की है।

विषय की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र ने 'आंतकवाद' विषय पर लेख आमंत्रित किये। नों उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख न केवल आंतकवाद के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत कर रहे हैं अपितु भारतीय राज्य की सुदृढ़ता तथा जम्मू व कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 व 35–ए के विशिष्ट प्रावधानों को नए रूप से अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं।

संश्लेषण के सप्तम अंक के समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन से संबंधित आधारभूत बिंदुओं को भी प्रकट करते हैं। लेखकों के विचार स्वतंत्र चिंतन के परिचायक हैं तथा सम्पादकीय मंडल ने इनकी मौलिकता को संपादन के माध्यम से किसी भी प्रकार प्रभावित व परिवर्तित करने का प्रयास नहीं किया है। व्यक्तिगत लेखों में प्रस्तुत तथ्य एवं मत लेखकों की रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करते हैं।

संश्लेषण के सप्तम अंक में प्रकाशित लेखों पर पाठकों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम वर्ष 2019 के मार्च माह के अपने तृतीय समसामयिक तथा महत्वपूर्ण अंक में और अधिक गुणवत्ता लाने का प्रयास करेंगे।

संपादक मंडल

बृहस्पतिवार, 14 मार्च 2019

1

आतंकवादः संक्षिप्त परिचय

निशा कुमारी
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

समकालीन विश्व में लगभग सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंडे में आतंकवाद प्राथमिकता का विषय बना हुआ है। वास्तव में आतंकवाद हमारे समय का सबसे बडी सुरक्षा चुनौती है तथा विभिन्न राज्य तथा सरकारें आतंकवाद को खत्म करने तथा इसका समाधान निकलने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। यह लेख आतंकवाद की परिभाषा तथा वैश्विक पटल पर इनकी प्रकृति सम्बन्धी संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करता है।

राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आतंकवाद के खतरे का विश्लेषण करने से पहले यह परिभाषित करना आवश्यक है कि आतंकवाद क्या है? तथा यह कैसे तथा किन रूपों में पाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद अपनी एक रिपोर्ट में आतंकवाद को इस शब्दों में परिभाषित करता है– 'ऐसे कोई भी क्रिया जिसका उद्देश्य किसी देश की नागरिक जनसँख्या को मारने या शारीरिक क्षति पहुचाने या किसी देश की सरकार या अंतरार्ष्ट्रीय संगठन को ऐसा करने या कुछ करने से रोकने के लिए विवश करने से सम्बंधित हो, आतंकवादी गतिविधि है'। अकादमिक जगत इस समस्या को अधिक जटिल रूप में देखता है। आतंकवाद की परिभाषा पर हुए एक अध्ययन के अनुसार अकामिक विद्वानों के मध्य आतंकवाद की 200 से भी अधिक भिन्न परिभाषाएं विद्यमान है। यद्यपि विश्व के अनेक विद्वानों ने आतंकवाद की सर्व–स्वीकृत परिभाषाओं को गढ़ने का प्रयास किया है परन्तु वह भी सर्व–स्वीकृत साबित होने में असफल रहीं हैं।

आतंकवाद की सबसे उपयोगी परिभाषा जो इसकी प्रकृति को स्पष्ट करती है वह इसे राजनितिक, मनोवैज्ञानिक, उत्पीड़क तथा सोच समझकर अंजाम दी गयी घटना बताती है। यह सोच समझकर की गयी घटना इसलिए है क्योकि यह समझदारी से युद्ध कौशल की योजना बनाकर विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु व्यवहार में लायी जाती है। उत्पीड़क इसलिए है क्योंकि यह हिंसा का प्रयोग करके अन्य को मारने या गहरी शारीरिक क्षति पहुचाने का कार्य करती है। यह मनोवैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि यह लक्षित जनसंख्या को मनोवैज्ञानिक रूप से डराने के लिए की जाती है तथा इसकी प्रकृति राजनितिक इसलिए क्योंकि ज्यादातर आतंकवादी गतिविधियाँ राजनितिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही की जाती है तथा राजनितिक प्रभाव उत्पन्न करते है। आतंकवाद का राजनितिक सन्दर्भ में विश्लेषण बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकतर आतंकवादी घटनाओं में यह राजनितिक उद्देश्यों से अभिप्रेरित होती है। यद्यपि उद्देश्य राजनितिक होते है परन्तु व्यापक दायरे में लोगो को अपील करने के लिए अपराधी इसे विचारध ाारात्मक तथा धार्मिक रूप देने में प्रयासरत रहते है। अतः इस प्रकार आतंवाद की गतिविधि को अन्य साधनों से लगातार युद्ध की स्थिति को लगातार बनाये रखने के साधन के रूप में भी चिन्हित किया जा सकता है।

आतंकवाद के विश्लेषण से जुडी हुयी बहुत सी समस्याएं है परन्तु सबसे महत्वपूर्ण इनकी प्ररणा तथा उद्देश्य की जानकारी का न होना है। इसी प्रकार इनकी संरचना, कार्यप्रणाली, तथा संगठन सम्बन्धी जानकारी का कम होना भी इस दिशा में एक महत्वपूर्ण चुनौती प्रस्तुत करता है। यद्यपि आतंकवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करना असंभव है जोकि सदियों से राजनितिक रूप से अभिप्रेरित हिंसक गतिविधि ा रही है। आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के क्रम में इसके उद्देश्यों, संगठन, व्यवहार और आतंकवादी समूहों की परिवर्तित होती युद्ध कौशल को सझना आवश्यक है। अब जनसँख्या, राज्य तथा सरकारों पर आतंकवाद के आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव उत्पन्न कर रहा है।

उन्नीसवी शताब्दी से पूर्व आतंकवादी सामान्य निर्दोष व्यक्तियों को क्षति नही पहुँचाने को प्राथमिकता देते थे। पान्तु समय के साथ इसमें परिवर्तन आया जिसे सितम्बर 11 के आतंकवादी हमले के उदाहरण में देखा जा सकता है। ऐतिहासिक रूप से देखे तो 1970 में आतंकवाद के पीछे की अभिप्रेरणा राजनितिक रहती है इसलिए विमान अपहरण, अपहरण, बमबारी इत्यादि अधिकतर व्यवहार में लायी जाने वाली पद्यतियां रहीं। परन्तु 1980 के दशक में राजनितिक रूप से अभिप्रेरित आतंकवाद के साथ ही धार्मिक तथा आर्थिक रूप से अभिप्रेरित आतंकवाद की भी उत्पत्ति देखी जाती है। 1990 के दशक में धार्मिक आतंकवाद एक नई घटना के रूप में उभरकर आता है। 1980 में रासायनिक हथियारों का प्रयोग भी इसमें जुड़ जाता है। 1990 में परंपरागत पद्यति के अतिरिक्त अन्य खतरे दिखाई देते हैं । इन्टरनेट के बढ़ते उपयोग के साथ आतंकवाद भी सूचनाओं की युद्धकला का उपयोग करने लगता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने आतंकवाद का दायरा विश्त्रित कर दिया है जहां तकनीक के विकास से आतंकवाद स्वयम का अंतरार्ष्ट्रीयकारण कर रहा है। 11 सितम्बर की घटना प्रकट करती है कि वैश्वीकरण के साथ इसके खतरे अधिक व्यापक हुए हैं।

भारत में 26ध्11 के हमलों ने आतंकवाद के प्रति भारतीय दृष्टि को परिवर्तित कर दिया। आतंकवाद का उद्भव तथा वृद्धि बहार की आन्तरिक सुरक्षा के लिए महत्पूर्ण चुनौती बनती जा रही है। आतंकवाद को कभी भी सिर्फ इसके हमले का तुरंत प्रतिक्रिया से रूप में कार्यवाही करने से समाप्त नही किया जा सकता यद्यपि इनके नेटवर्क को निरंतर लक्षित करने तथा तबाह करने की आवश्यकता है। अतः आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सुरक्षात्मक कार्यों को शामिल करते हुए प्रभावशाली आतंकी विरोधी योजना को व्यवहार में लाने की आवश्यकता है।

♦♦♦♦♦

2

आतंकवादः विश्व जगत की विकराल समस्या

शिम्पी पांडे
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

आतंकवाद शब्द का प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में अस्तित्व में आया और 20वीं शताब्दी के अंत में यह विश्वपटल पर व्यापक रूप से उभरकर सामने आया । आतंकवाद को शब्दों में परिभाषित करना जटिल कार्य है क्योंकि इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है । इसके बहुस्तरीय हानिकारक प्रभाव हैं और बहुस्तरीय कारक आतंकी घटनाओं के लिए उत्तरदायी हैं[५] आतंकी घटनाएं भय और अस्थिरता उत्पन्न करती हैं । यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण विषय बन गया है ।

आतंकवादी हिंसा के द्वारा राज्य और समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करना, आंतरिक व बाह्य क्षेत्र में भय, राज्य की शांति व्यवस्था भंग करना, राजनीतिक अस्थिरता राज्य की आंतरिक व्यवस्था को शिथिल करना आतंकवादियों का उद्देश्य बन गया है। राजनीतिक हिंसा, हत्या, अलगाववाद, सैन्यवाद, सांप्रदायिक हिंसा, विरोध, उग्रवाद, नृजातीय हिंसा इत्यादि आतंकवाद के परिणाम हैं । यह राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं । राजनीतिक स्वतंत्रता, रुढ़िवादी राजनीतिक संस्थाएं और सांस्कृतिक मूल्य आतंकवादियों के निशाने पर होते हैं।

आतंकवादी घटनाओं का निरंतर घटित होना मानव अधिकारों के हनन को भी उजागर करता है, जिसमें निर्दोष महिलायें, पुरुष, वृद्ध, बच्चे इत्यादि सभी इसे प्रभावित होते हैं और सैकड़ों की संख्या में मारे जाते हैं । यद्यपि इससे मात्र शांति–व्यवस्था का ही हनन ही नहीं होता बल्कि यह सम्पूर्ण मानवजाति के मूल्यों का भी विनाश करता है । यदि हाल के वर्षों का अध्ययन किया जाए तो यह प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित होता है कि आतंकवाद का विस्तार विभिन्न देशों में राजनीतिक अस्थिरता लाने, और भय का वातावरण पैदा करने के उद्देश्य से किया जाता है।

21वीं शताब्दी में देश के विभिन्न देशों में घटित होने वाली आतंकी घटनाएं इस समस्या के विकराल स्वरुप को प्रतीत करते हैं। समकालीन विश्व जगत में आतंकवाद एक ज्वलंत समस्या है व इससे संपूर्ण विश्व प्रभावित हो रहा है । विकसित, विकासशील एवं अन्य सभी देश इस विकराल समस्या से ग्रसित हैं। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के 9/11 (11 सितंबर, 2011) के आतंकवादी हमले के बाद विश्व जगत इस समस्या इस समस्या के प्रति अत्यधिक जागरुक हुआ और इस समस्या पर गंभीरता से विचार किया । अमेरिका के आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध (वॉर अगेंस्ट टेररिज्म) इसी दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरोध में विश्व पटल पर अधिकांश देशों को आतंकवाद के विरोध में एकजुट कर दिया । इस समस्या का समाधान करने हेतु विभिन्न कदम उठाये गए ।

दक्षिण एशिया में समय–समय पर होने वाली विभिन्न आतंकवादी घटनाएं इस बात का सूचक है कि यहां भी आतंकवाद का व्यापक दुष्प्रभाव हुआ है । यद्यपि भारत में आतंकवादी घटनाओं में पिछले दो दशकों में अप्रत्याशित रूप से अत्यधिक वृद्धि देखि गई है । इनके निवारण हेतु भो ठोस कदम उठाये गए हैं किंतु अब भी इसका निवारण नहीं किया जा सका और ना ही कोई शसक्त और सुनिश्चित नीतियां ही इसे समाप्त करने में प्रभावी सिद्ध हुई हैं। भारत की संसद पर 13 दिसंबर, 2001 में, और 26/11 (26 नवंबर, 2008) में मुंबई के ताज होटल पर आतंकवादी एवं निरंतर होने वाला सीमा–पार आतंकवाद, संघर्ष–विराम का उल्लंघन व अन्य सभी आतंकवादी घटनायें इस बात को सिद्ध करती हैं कि आतंकवाद अति विकराल और भयावह रूप धारण कर रहा है । इन आतंकवादी हमलों ने ना केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को भी झकझोर दिया ।

यद्यपि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता किंतु आतंवादी घटनाओं का राजनीतिकरण कहीं न कहीं इसे धर्म से संलग्न कर देते हैं । यह भी सत्य है कि विभिन्न आतंकवादी संगठनों के नेता इस्लामिक देशों के हैं और विभिन्न आतंकवादी का केंद्र और आधार भी उन्हीं देशों में पाया जाता है । समकालीन आतंकी संगठन मुख्य रूप से युवाओं को उग्रवाद की ओर धकेलते हैं और साथ ही रुढ़िवादी/उग्रवादी संगठन धर्म के नाम पर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देते हैं । विभिन्न आतंकी संगठन जैसे अल–क़ायदा, जैश–ए–मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन इत्यादि अति महत्वपूर्ण आतंकी संगठन हैं जो विभिन्न देशों में दहशत और आतंक का प्रसार करते हैं ।

आतंकी संगठन जैश–ए–मोहम्मद के संस्थापक मसूद अज़हर की आतंकी गतिविधियां मुख्य रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में संचालित की जाती हैं और समय–समय पर भारत के भू–भाग में भी विभिन्न आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया है व विश्व के अन्य कई क्षेत्रों में भी इसके द्वारा विभिन्न आतंकी गतिविधियां निरंतर संचालित की जाती हैं । विश्व पटल पर भारत के द्वारा मसूद अज़हर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किये जाने की मांग की जाती है जिसमे भारत को चीन का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ है । जिस प्रकार अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन के विरुद्ध कार्यवाही की और उसका अंत किया, उसी प्रकार आवश्यकता है भारत भी वह ठोस कदम उठाये और विभिन्न आतंकी घटनाओं पर नियंत्रण करे और उसका निवारण करे ।

कश्मीर की समस्या और सीमापार आतंकवाद

भारत–पाकिस्तान के मध्य कश्मीर की समस्या विभाजन के पश्चात से ही एक ज्वलंत समस्या के रूप में निरंतर विद्यमान है । कश्मीर पर अधिपत्य को लेकर पकिस्तान सदैव भारत के लिए विवाद व द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न करता है[५] पाकिस्तान द्वारा जम्मू–कश्मीर की सीमा में हस्तक्षेप विभाजन के उपरांत से ही किया जा रहा है और राज्यकृत आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है । पाकिस्तान का राज्यकृ त आतंकवाद के निशाने पर भारतीय लोकतंत्र और उसका सेकूलर चरित्र है जिसे कमज़ोर करना आतंकवादियों का लक्ष्य होता है । यद्यपि भारत की सेना की नीति रक्षात्मक है,

अतः यह कभी आक्रामक रवैया नहीं अपनाता[५] किंतु पाकिस्तान का निरंतर किया जाने वाला संघर्ष–विराम का उल्लंघन अब भारत को नीतियों में परिवर्तन की आवश्यकता को उजागर करता है[५]

वर्तमान स्थिति अब इस प्रकार हो गई है की भारत अब आक्रामक नीतियों का अनुसरण करे और आतंकी घटनाओं पर विराम लगाये जायें।

भारत की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सेना का सदैव महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतीय सेना के द्वारा समय–समय पर भारतीय सीमा की सुरक्षा हेतु आतंकी संगठनों और आतंकवादियों का विनाश और ठोस कदम उठाये जाते हैं। भारतीय सेना को आतंकी घटनाओं के अंत में सफलता प्राप्त होती है व साथ ही कई बार भारतीय सेना के कई जवान शहीद हो जाते हैं। देश की सीमा में आने वाले आवांछनीय आतंकवादियों के विरुद्ध सेना ठोस कदम उठाती है जिससे देश की आंतरिक व बाह्य क्षेत्र में शांति व व्यवस्था बनी रहे। सीमा–पार आतंकी गतिविधियों में कमी की अपेक्षा निरंतर वृद्धि हो रही है जिनका निवारण किया जाना अति–आवश्यक है। पाकिस्तान के द्वारा भारत के विभिन्न भागों जैसे उत्तर–पूर्व, जम्मू–कश्मीर, पंजाब व अन्य कई राज्यों में आतंकी घटनाओं और राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न करते हैं।

हाल ही में कश्मीर के पुलवामा में 14 फ़रवरी, 2019 के आतंकी हमले में 40 भारतीय जवानों की मृत्यु हो गई जो इस बात का ज्वलंत उदाहरण है कि सीमा पर आतंकी घटनायें भारत की शांति–व्यवस्था को भंग करने के उद्देश्य से की जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष यह एक महत्वपूर्ण समस्या है की आतंकवाद की रोकथाम की जाये। भारत के द्वारा पुलवामा हमले की जवाबी कार्यवाही स्वरुप पाकिस्तान के बालाकोट में 26 फ़रवरी, 2019 को विभिन्न आतंकी संगठनों पर भारतीय वायु सेना के द्वारा हवाई हमला किया गया जिसमें व्यापक संख्या में आतंकवादी मारे गए।

यद्यपि आवश्यकता है कि अब राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के विरुद्ध शसक्त नीतियों का निर्माण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर किया जाए। आतंकवाद एक विश्व्यापी समस्या बन गई है जिससे विश्व के अधिकांश देश प्रभावित हो रहे हैं। अतः वैश्विक स्तर पर आवश्यकता है कि विभिन्न देश एकजुट होकर आतंकवाद के विरुद्ध ठोस कदम उठायें।

♦♦♦♦♦

3

आतंकवादः कारण एवं समाधान

दिव्या राणा
शोधार्थी, सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

आतंकवाद, आधुनिक दुनिया का ऐसा वायरस, जिससे भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व संकटग्रस्त है। आतंकवाद लोकतांत्रिक संस्था की सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण समस्याओं में से एक है तथा देश के विकास, आर्थिक, और राजनीतिक स्थिरता को कम करता है। अमेरिका, ब्रिटेन और फांस जैसे देश जो खुद को इससे अछूत मानते थे आज आतंकवाद के भयावह रूप को देख रहे हैं।

आतंकवाद को कैसे परिभाषित करे, इस पर विश्व स्तर पर अभी तक सहमति नही बन पाई है, क्योंकि कोई इसे अपने ढंग से समझता है। भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई के समय अंग्रेज, स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकवादी समझते थे जबकि वे तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। साउथ अफीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मडेला को भी अपने देश की आजादी की लड़ाई के दौरान आतंकवादी कहा जाता था। ब्रिटिश शासन काल मे डा. बी.आर. अम्बेडकर को दलितों और पिछड़ों के हक की मांग के लिए हिन्दू सवर्णो द्वारा देशद्रोही कहा गया। कई बार हक की लड़ाई लड़ने वाला उग्र हो जाता है, उसे सामने वाला आतंकवादी समझ लेता है। हर हिंसा करने वाला आतंकवादी नही होता, लेकिन हर अहिंसावादी अतंकवादी न हो ये भी जरूरी नही है। फिर भी आतंकवाद के निम्न प्रकार देखे जा सकते हैं – (1). राज्य प्रायोजित आतंकवाद – एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर आतंकवादी कार्यवाई (2). असहमति आतंकवाद – अपनी सरकार के खिलाफ आतंकवाद (3). धार्मिक आतंकवाद (4). अपराधी आतंकवाद (5). राजनीतिक विचार धारा में समाहित आतंकवाद।

आतंकवाद 21 वीं शताब्दी की घटना नही है बल्कि इसकी जड़े प्रथम शताब्दी में सीकरी (पबंतपप) आतंकवादी संगठन के रूप देखी गई, जो कि रोमन पेशे का विरोध करता था। आधुनिक आतंकवाद का उदय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोपिय शक्तियों के पुराने शासन में राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में हुई। 11 सितम्बर 2001 को यू.एस.ए. की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए आतंकी हमले को विश्व इतिहास का टर्निंग प्वाइंट माना गया और आतंक पर लड़ाई (त वद ज्मततवत) की शुरूआत मानी गई। इसके बाद 'आतंक पर लड़ाई' 2001 में अफगानिस्तान तथा 2003 में इराक में हुई। 11 सितम्बर 2001 की घटना के बाद आतंकवाद मुस्लिम बाहुल्य देशों में संकेन्द्रित हो गई। फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित देश–इराक, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, भारत, सोमालिया, इजिप्ट और लीबिया है।

भारत में नक्सलवादियों के रूप में पहली बार आतंकवाद पश्चिम बंगाल के गॉव नक्सलबाड़ी में 1967 में भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार के नेतृत्व में देखा गया। यह एक किसान विद्रोह, स्थानीय जमीदार के शोषण के खिलाफ सशस्त्र कार्यवाई थी। 'जमीन जोतने वाले' की यह नारा पहले

से लोकप्रिय था। वे मानते थे कि भारतीय मजदूरों और किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जिम्मेदार हैं। शुरूआत में आंदोलन का उद्देश्य सही लगता है, लेकिन जब आंदोलन का नेत्त्व गलत हाथों में चला जाता है तब वे आंदोलन के उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं और मनमानी ठंग से सरकार पर दबाव बनाते हैं। सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित जिले को प्रदान किये गये पैसे को सही ठंग से खर्च किया जाये तो राज्य की तस्वीर बदल सकती है। मगर अफसोस ये पैसा नेताओं, अफसरों, ठेकेदारों और नक्सलियों के बीच बंट जाता है। आज नक्सली आंदोलन ने पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, ओडिसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया।

सरकार को सबक लेना चाहिए कि जब राजीव गांधी ने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया तो साथ में बाजार को ताला भी खोला गया। इसी के साथ दो किस्म के कट्टरपथ को खड़ा किया गया, एक इस्लामी आतंकवाद और दूसरा माओवाद। 2009 में भारत सरकार ने सीपीआई (माओवादी) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। माना जाता है कि कॉरपोरेट कंपनियां आदिवासी इलाकों में खनन गतिविधियां हर हाल में बढ़ाना चाहती है। विकास दर बढ़ाने को बेचैन सरकार चै। कानून और संविधान की पांचवी अनुसूची का भी ख्याल नही है जो आदिवासियों की इच्छा को सर्वोपरि मानता है। लेकिन माओवादी इस राह में रोड़ा बने हुए है, जिसके कारण माओवादियों का पुलिस और सुरक्षाबलों के साथ हिसक लड़ाई होती रहती है। सरकार माओवादीयों को आतंकवादी बताते हुए कहती है कि वे आदिवासियों की जिन्दगी दूभर बना रहे है। उधर माओवादी सरकार को जल, जंगल और जमीन का लूटेरा बताते है जो कॉरपोरेट कंपनियों के लिए आदिवासियों का संहार कर रही है। अरूंधती राय ने यूपीए–2 के 'आपरेशन ग्रीनहंट' के दिनों में जंगलों में कई दिन माओवादी गुरिल्लों के साथ बिताया था और अपने लेख 'वाकिंग विद कामरेड्स' के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समस्या की ओर ध्यान खींचा था।

लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने संपूर्ण कांति में न्याय की मांग की थी। जैसे – जमीन जोतने वाले की हो या सम्पत्ति का समान वितरण। लेकिन आज जो माओवादी सबसे 'रेडिकल' कहलाते हैं, वे बस यही तो कह रहे हैं कि जो जमीन आदिवासियों के पास है, उसे छीना ना जाये। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 13 फरवरी 2019 के आदेश के अनुसार भारत के 17 राज्यों के वन क्षेत्रों में फैले लगभग दो मिलियन आदिवासी लोगों को जबरन बेदखल करने का निर्देश दिया। दलित उत्पीड़न के खिलाफ 02/04/2018 को दलितों के भारत बंद के दौरान कई दलितों की हत्या हुई और जेलों में भी डाला गया। ऐसा लगता है कि सरकार ने 'न्याय' के विचार को दरकिनार कर दिया है। अगर सरकार ने इन मुद्दों को गम्भीरता से नही लिया तो आने वाले समय में ये लोग सशस्त्र आंदोलन की शुरूआत कर सकते हैं। मोहम्मद युनुस (नोबेल शांति पुरस्कार विजेता) के अनुसार आतंकवाद को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमें इसके मूल कारणों को सम्बोधित करना चाहिए। इनका मानना है कि बंदूकों पर खर्च करने की बजाय संसाधनों को गरीब लोगों का जीवन सुधारने में लगाना एक बेहतर रणनीति है।

भारत में आतंकवादी हमले की सूची लम्बी ही होती जा रही है। कुछ बड़े हमले इस प्रकार है – मुंबई आतंकी हमला (26/11/2008), भारतीय संसद पर हमला (13/12/2001), मुंबइ सीरियल ब्लास्ट

(12/03/1993), मुंबई ट्रेन धमाका (11/07/2006), अक्षरधाम मंदिर पर हमला (24/09/2002), दिल्ली सीरियल बम ब्लास्ट (29/10/2005), जयपुर ब्लास्ट (13/05/2008), असम में धमाके (30/10/2008), जम्मू कश्मीर विधानसभा भवन पर हमला (01/10/2001), गुरदासपुर हमला (27/07/2015), इंदिरा गॉधी और राजीव गॉधी की हत्या आदि। अभी हाल में, 14/02/2019 को पुलवामा (जम्मू कश्मीर) में भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले वाहनो के काफिले पर जैश–ए–मोहम्मद इस्लामी आतंकवाद समूह द्वारा आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 40 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के सुरक्षा कर्मियों की जान गई। इसके लिए भारतीय सरकार को पाकिस्तान को दोष देने के बजाय भारतीय प्रशासनिक तंत्र तथा खुफिया एजेंसी को और मजबूत करना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रस्त है। 2015 में पाकिस्तान में करांची के स्कूल में कुछ आतंकवादी घुसकर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे कई बच्चे और शिक्षक मारे गये थे। कश्मीर को लेकर भारत पाकिस्तान की लड़ाई अब बड़ा रूप ले चुकी है। 1999 में कारगिल की लड़ाई इसी का रूप थी। कश्मीर को भारत में आतंकवाद का गढ़ माना जाता है, धरती का स्वर्ग कश्मीर में आज लोग जाने से डरते हैं।

भ्रष्टाचार, जातिवाद, आर्थिक विषमता, भाषा का मतभेद, बेरोजगारी, हिन्दू–मुस्लिम दंगे, दलितों पर अत्याचार, ये सब आतंकवाद के मूल तत्व हैं। इन्हीं के बाद आतंकवाद पनपता है। आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार को उपर्युक्त मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। धर्म को सही ढंग से समझना होगा। हमें धर्म जाति के ऊपर इंसानियत को रखना चाहिए। इसके अळावा सीमा प्रबंधन; समान नागरिक संहिता; आतंकवादियों के लिए फास्ट–ट्रैक अदालतों का प्रावधान; गैर सरकारी संगठनों के कामकाज का मूल्यांकन; सशस्त्र बलों और नागरिकों के बीच सद्भाव; सुरक्षा बलों को संगठनात्मक समर्थन; भारत के नागरिकों में जागरूकता; अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहन; राजनयिक पहल; आतंकवाद पर विदेशी नीतियों को अपनाना; आतंकवादी का प्रत्यर्पण या अभियोजन; आतंकवाद पर द्विपक्षीय संधियों का निष्कर्ष, आतंकवाद पर आपसी सहयोग; मानव अधिकारो का संरक्षण आदि विषयों पर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। आतंकवाद को दूर करने के लिए अच्छी शिक्षा की बहुत जरूरत है। भारतीय संविधान के प्रति लोगों में अटूट विश्वास पैदा करना होगा तथा संविधान को सही ढंग से लागू करना होगा। आतंकवाद से निपटने के लिए देश दुनिया को मिलकर काम करना होगा, और इसलिए हर साल 21 मई को 'आतंकवाद विरोधी दिवस' मनाया जाता है।

♦♦♦♦♦

4

धर्म एवं आतंकवादः इस्लामिक आतंकवाद के संदर्भ में

राहुल शर्मा
राजनीति विज्ञान, दिल्ली विश्वविद्यालय

लम्बे समय से इस विषय पर कई बड़ी–बड़ी चर्चाएँ हो चुकी है कि क्या आतंक का कोई धर्म होता है? या नहीं. हमारी चर्चा का विषय भी यही से ही शुरू होता है जनसाधारण में यह चर्चा इसलिए ज्यादा जोर पकड़ती है क्योंकि अधिकतर लोग इस बात पर तो सहमत होते है की आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जब भी कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है तो उसका सम्बन्ध जिस धर्म से होता है वो तो इस्लाम ही होता है। बस यही से यह चर्चा बहुत गर्म हो जाती है। इसे लेकर लोगों के कई दृष्टिकोण हो सकते है, कुछ इसे धर्म से जोड़कर देखते है, तो कुछ इसे धर्म से अलग देखते है, सही उत्तर तक पहुचने के लिए कुछ बुनियादी सवालों के जरिये हम काफी कुछ समझ सकते है।

इसी दिशा में जब हम आगे बढ़ते है तो बड़ा सवाल यह आता है कि क्या कोई भी धर्म, अन्य धर्म के प्रति घिर्णा का उपदेश दे सकता है। जबकि प्रत्येक धर्म में जो शिक्षा दी गयी है, उसके आधार पर आपसी प्रेम, शान्ति, बंधुत्व, सौहार्द, और कमजोरों की सहायता, मानवता के मार्ग पर चलना और अन्याय का विरोध करना ही धर्म है, लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते है तो पाते है कि यह धर्म ही है जिसके कारण इसे सबसे ज्यादा आतंकवाद को बढ़ावा भी मिल रहा है तो यह जानना बहुत जरूरी भी है की यह विरोधाभास कहाँ से जन्म ले रहा है।

कुछ लोग है जो अपने आतंकी लक्ष्य तक पहुचने के लिए धर्म को अपना जरिया बनाते है, ऐसा वे इसलिए करते है क्योंकि धर्म की आड़ में ही उन्हें समाज के बीच रहकर ही इस प्रकार की सुरक्षा और पनाह मिलती है जिससे वे लोगों के बीच में ही दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सकते है और इसी बात का फायदा उठाने के लिए आतंकी धर्म का आँचल ओढ़े रखते है।

इस्लामिक आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ईसाई आतंकवाद जैसे शब्दों के प्रयोग भर से ही चार प्रकार के संदर्भ स्थापित हो जाते है। पहला तो यह की आतंवाद का धर्म से सम्बन्ध होता है, दूसरा यह कि इसके माध्यम से धर्म के शुद्ध रूप को बदनाम किया जाता है, तीसरा यह की इसके राजनैतिक फायदे लिए जा सकते है, और चौथा यह कि इससे हमारे देश की अखंडता को चुनौती दी जाती है। हमे इन धार्मिक आतंकवाद के शब्दों को तुरंत अपने शब्दकोष से निकालकर फेंक देना चाहिए क्योंकि हमारा देश लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संविधानवाद, विधि का शासन, शांति और धर्म–निरपेक्षता पर चलने वाला देश है, जो पुरे विश्व में शांति संदेश देता है इसलिए हमारे देश में इस प्रकार के शब्द होने ही नहीं चाहिए. इस शब्द के प्रयोग से देश की सामाजिक व्यवस्था में विभाजन पैदा होता है।

धर्म को, आतंकवाद के लिए कारण बताने वाले लोगों की निंदा होनी चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पर आतंक की शुरुआत किशोरों के दिमाग में धर्म से जुड़ी भ्रामकताएँ पैदा करके की जाती है, धर्म अपनेआप में गलत नहीं है बल्कि धर्म की गलत व्याख्या को धारण करने वाले लोग गलत है। वे भूल जाते है की भारत ही एक अकेला ऐसा देश है जहाँ मुस्लिम अपने मत का सार्थक व अर्थपूर्ण प्रयोग कर सकते है और अपने समाज के प्रति अपना कर्तव्य व्यक्त कर सकते है।

आतंकवाद आज, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है तीखी बहस इस चीज़ की भी छिड़ी हुई है की कौन देशद्रोही है? और कौन देशभक्त राष्ट्रवादी? जिसे प्रमाणित करने की होड़ में सामाजिक भाईचारा प्रभावित हो रहा है इसके साथ समस्या एक यह भी है की हमारे देश में आज भी ऐसे कई लोग है जो द्वि–राष्ट्र सिद्धांत आज भी अपने मन में पाले हुए बैठे है जोकि वर्तमान समय में किसी आतंकवादी मनसूबे से कम नहीं है। इसी के साथ धर्म के नाम पर नफरत और गलतफ़हमी भी फैलाई जाती है जब भी किसी धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है तो अन्य धर्मों के भीतर अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने जैसी भावनाएँ जन्म लेतीं ही है। और आतंकवाद के बीज बो दिए जाते है।

जैश–ए–मोहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा, और कई अन्य संघठन धर्म को केवल आतंक फ़ैलाने के लिए, और अपने आकाओं को खुश करने के लिए, केवल इस्लाम धर्म को केवल साधन के रूप में ही देखते है। ये लोग कुरान जैसे पाक साफ़ ग्रन्थ को भी नही छोड़ते किसी के क़त्ल को सही साबित करने के लिये, पराकाष्ठा तो तब हो जाती है, जब आतंक के आका खुद को खलीफा घोषित कर देते है जबकि इस्लाम में खालिफा जैसे शब्द का विवरण कही पर है भी नहीं। आतंकवाद को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि यदि आतंकवादियों के हाथ परमाणु हथियार लग गए तो पता नहीं क्या होगा? इसे रोकने के लिए हमारी सरकारें निरंतर प्रयास कर रही है।

लेकिन राजनीति में फायदे के लिए, समाज को बांटने के लिए और धर्म की आड़ में स्वार्थ की दुकानदारी चलाने के लिए यही प्रचार किया जाता रहा है कि आतंकवाद का संबंध धर्म से होता है। ऐसा कहने वाले अपनी सुविधा के मुताबिक आतंकी घटनाओं की समीक्षा करते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए वे भूल जाते हैं कि हर बार मरने वाला आम इंसान ही होता है। आतंकवाद चाहे जिस धर्म के नाम पर फैलाया जाए, अंततरू वह इंसानियत का ही खात्मा करता है।

हमारे ही देश में एक नयी पीढ़ी ऐसी भी आ गयी है जो अपनेआप को इस देश का हिस्सा मानते ही नहीं है। ये वो लोग है जो वन्दे मातरम बोलने से भी कतराने लगे है, तो यह समझ लेना चाहिए की उन्होंने अब भारतीयता की भावना का त्याग कर दिया है। इनमे वो लोग भी शामिल है जो बईमान बुद्धिजीवी वर्ग से सम्बन्ध रखते है जो टीवी के सामने माइक पर कुछ और, और राजनैतिक चुनाव के समय कुछ–की–कुछ बातें करतें है, इन्हें बईमान बुद्धिजीवी वर्ग कहना ही ठीक होगा क्योंकि ये वन्दे मातरम् केवल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि ऐसा करने के लिए संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इंसानियत और ईमानदारी नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हमें अपने देश के प्रति वफादार बनाती है।

गजवा–ए–हिन्द बनाम हिन्दू राष्ट्र की लडाई, ऐसी स्तिथि को जन्म देती है जिसमे आपसी सौहार्दबिगड़ता तो है ही यह भी सम्भव हो जाता है कि आतंक की नयी शाखा यहाँ से भी जन्म ले सकती है जिसने इस आतंकवाद को पाला–पोसा है आज वही देश (पाकिस्तान,अफगानिस्तान,सीरिया,ईरान,इराक,बांग्लादेश) इसकी मार सबसे ज्यादा झेल रहे है। रोजाना स्कूल में बच्चों को मारा जा रहा है, मस्जिदो को उड़ाया जा रहा है। यह कैसा जिहाद है जो मासूम बच्चों और औरतों को भी नहीं बक्शता।

कुछ देश तो आतंकवाद को बढ़ाने में मदद भी कर रहे हैं उदाहारण के लिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में, कई आतंक प्रायोजित संगठन छोटे–छोटे बच्चों को सिपाही के रूप में भर्ती करते है जिससे उनको प्रशिक्षित करके आत्मघाती बम विस्फोट द्वारा मंदिर. मस्जिद, राष्ट्रिय पवीं पर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों को अपना निशाना बनाया जा सके, इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी का नया चलन शुरु किया है। लेकिन उसका शिकार अन्य धर्म के लोगों के साथ इस्लाम का शिद्दत और ईमानदारी से पालन करने वाले लोग भी होते हैं। इसलिए धर्म की सेवा का तर्क यहां सिरे से खारिज होता है।

आज जो हाल हमारे कश्मीर में है कि नवयुवको को पैसा देकर किस तरह देश और सेना के ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है पत्थरबाज बनाया जा रहा है उसके लिए कही ना कही धर्म की गलत व्याख्या ही जिम्मेदार है ! अतः हम सभी को बड़ी समझदारी के साथ बन्धुत्व बनाये रखना चाहिए. सबसे पहले हमारा कर्तव्य है एक जिम्मेदार नागरिक होना, देश की तरक्की के लिए खुद को आगे बढ़ाना, देश में पैदा होने वाले पहचान के संकट का विवेकशीलता से सामना करना, और इसके साथ ही हमे एक अवधारणा बिलकुल स्पष्ट कर देनी चाहिए की जो व्यक्ति आतंक के रस्ते को अपनाता है, वह मानवता को शर्मसार करता है वह व्यक्ति वाकई में मानव कहलाने योग्य है ही नही. क्योंकी ऐसे व्यक्ति का धर्म जो मानवता के मूल्यों से रहित है वह धर्म हो ही नहीं सकता।

♦♦♦♦♦

5

भारत के लिए बाहरी आतंकवाद प्रमुख चुनौतीः सॉफट पॉवर द्वारा समाधान

रोहित कुमार
शोधार्थी, इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

समकालीन परिपेक्ष्य में आतंकवाद पूरे 'विश्व समुदाय' के सम्मुख गैर–राज्य अभिनेता के रूप में सबसे जटिल चुनौतियां उत्पन्न कर रहा है, कोई भी मानव आवास सुविधा से परिपूर्ण (अपवाद अंटार्कटिका) महाद्वीप इसके प्रभाव से अछूता नहीं है, हालांकि सबसे प्रमुख चुनौती मुख्यतः 'अफ्रीका और एशिया' जैसे महाद्वीपों के समक्ष हैं, आतंकवाद इनके सामाजिक–आर्थिक विकास गतिविधियों पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। यद्यपि आतंकवाद की एक सर्वमान्य परिभाषा करना असंभव प्रतीत होता है क्योंकि आतंकवाद एक गैर–राज्य अभिनेता के साथ राज्य सरकारों के प्रायोजन से भी विस्तारित हो रहा है। इसका स्पष्ट उदाहरण भारत का पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित होना। इसका प्रमाण पेरिस स्थित, वित्तीय एक्शन टास्क फोर्स का पाकिस्तान को 'ग्रे–श्रेणी' में डालना, इस श्रेणी में उन देशों को सम्मिलित किया जाता है जो आतंकवाद वितीय फंडिंग गतिविधियों को रोकने एवं इसके अंत में वैश्विक सहयोग प्रदान नहीं करते हालांकि एफटीएफ ने पाकिस्तान को मई 2019 तक की समय सीमा तय कर चेतावनी दी है कि अगर पर्याप्त कदम नहीं उठाए तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।

अंतरराष्ट्रीय मंच एवं घरेलू स्तर पर भारत एवं अन्य देशों द्वारा यह प्रसारित किया जाता है कि "आतंकवाद का कोई धर्म एवं कोई प्रसांगिक विचारधारा" नहीं होती परंतु जब हम सैम्युल हंटिंगटन की पुस्तक 'सभ्यताओं का अंत'(ब्लैं व ब्पअपसप्रंजपवदे) की समीक्षा करें तो, इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि वर्तमान में होने वाले आतंकी घटनाओं का कहीं ना कहीं आधारित नेटवर्क "धार्मिक एवं सांस्कृ तिक मान्यता एवं पहचान" से जुड़ा हुआ है। अपनी इस पुस्तक में हंटिंगटन ने संकल्पना प्रस्तुत की है कि शीतयुद्ध उपरांत युग में वैश्विक संघर्ष का प्राथमिक स्रोत 'धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान के लिए आपसी मानवीय संघर्ष' होगे, जिसमें धर्म एवं संस्कृति श्रेष्ठता की अहंवाद विचारधारा प्रमुख होगी। इसका ज्वलंत उदाहरण न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च शहर में दो मस्जिदों पर आतंकी हमला व 49 बेकसूर लोगों की मृत्यु है।

भारत के संदर्भ में देखे तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद कहीं ना कहीं धार्मिक मान्यताओं एवं पहचान श्रेष्ठता की विचारधारा से भी जुड़ा है। इसका वर्णन हम जोसेफ न्ये (श्रवेमची छलम) द्वारा प्रतिपादित सॉफ्ट पावर सिद्धांत से समझने का प्रयत्न करेंगे, जो कहते हैं की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में त्रिआयामी चुनौतियां हैं जिन्हें पार कर ही शांति एवं विकास संभव है। प्रथम स्तर पर मिलिट्री चुनौती आती है जिससे विषय प्रभावित होता है, दूसरी चुनौती आर्थिक वही तीसरी है जो सबसे न्यूनतम स्तर की परंतु सबसे घातक चुनौती है जिसमें एक नहीं कई चुनौतियां विद्यमान है, जिससे पूरा विश्व कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है जैसे आतंकवाद, मानवाधिकार

हनन इत्यादि। इसका विस्तार राज्य और गैर–राज्य अभिनेता दोनों द्वारा होता है हालांकि इस चुनौती से सरलता से नहीं निपटा नहीं जा सकता बल्कि हार्ड पॉवर (मिलिट्री) प्रकार की शक्ति के साथ सॉफ्ट पॉवर शक्ति भी आवश्यकता है अर्थात् अंतरराष्ट्रीय संबंधों में दबाव, धमकी के स्थान पर "अनुनय एवं आकर्षण" की शक्ति यानि सॉफ्ट पॉवर की वकालत भी की जानी चाहिए, जिसका संसाधन संस्कृति, राजनीतिक मूल्य एवं विदेशी नीति आकर्षणता द्वारा दूसरे देश, समूह को अपनी ओर आकर्षित करना है।

साधारण शब्दों में सरकारों को "सोशल नेटवर्क"(सॉफ्ट पॉवर) का उपयोग दूसरे देशों से संबंध बढ़ोतरी में करना चाहिए यद्यपि हम गहराई से अध्ययन करें तो सॉफ्ट पावर संस्कृति धर्म प्रभाव आकर्षणता का उपयोग केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि आतंकी संगठन भी इन धार्मिक एवं सांस्कृतिक विचारों का उपयोग अपने निजी हितों के अनुरूप व्याख्यायित कर, समान धार्मिक मान्यताओं से जुड़े लोगों में मुख्यतः युवा पीढ़ी को आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित करने हेतु उपयोग कर रहे हैं। अल कायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन इसी सॉफ्ट पावर आयाम से भारत में आतंकी गतिविधियां चला रहे हैं अर्थात भारत को चाहिए कि न्छ जैसे मंचों से एक आतंकी सर्वमान्य परिभाषा एवं आतंक के अंत के लिए एक समान नीति निर्माण प्रयास के स्थान पर आतंकी गतिविधियों से देश को मुक्त कराने के लिए सॉफ्ट पॉवर आयाम का उपयोग करें क्योंकि चीन संयुक्त परिषद का स्थाई सदस्य होने के नाते हमेशा अपनी वीटो पॉवर कूटनीति पर कायम रहेगा एवं पाकिस्तानी समर्थन जारी रखेगा।

क्योंकि भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर मुस्लिम जनसंख्या बहुल देश है जिसका लाभ भारत सॉफ्ट पॉवर के रूप में कर, विश्व में मुस्लिम देशों की प्रमुख संस्था "इस्लामिक सहयोग संगठन" में सदस्यता प्राप्ति के लिए करें क्योंकि यह इस्लामिक संगठन सामाजिक–आर्थिक मुद्दों के साथ सांस्कृतिक संगठन भी है। जिसमें विश्व के 59 मुस्लिम देश शामिल है, साथ ही इसमें कई बड़े प्रभावकारी देश, संयुक्त राज्य अमीरात, सऊदी अरब जैसे देश भारत के सहयोगी भी हैं। भारत इसका उपयोग पाकिस्तान पर दबाव बनाने के रूप में कर सकता है हालांकि भारत की सदस्यता का पुरजोर विरोध पाकिस्तान करता है, जिसका उदाहरण मार्च में हुए संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत का अतिथि के तौर पर शामिल होने के विरोध में पाकिस्तान में सत्र का बहिष्कार किया। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने संबोधन में कहा कि 'आतंकवाद और चरमपंथ में अंतर होता है' सबको इस अंतर को समझना चाहिए। यह अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान पर निशाना था। भारत को अपनी संस्कृति एवं मिली–जुली धार्मिक विविधता में मुख्यतः मुस्लिम जनसंख्या(सॉफ्ट पॉवर) का लाभ उठाकर संगठन में सदस्यता पाकर पाकिस्तान को काउंटर कर, आतंक रोकने में मदद लेनी चाहिए क्योंकि इससे पाकिस्तान सरकार पर प्रभाव पड़ेगा और वह आतंकियों को वित्तीय एवं अन्य संयोग बंद करेगा। यह सॉफ्ट पॉवर कूटनीति, हार्ड पॉवर के विपरित ज्यादा अनुकूल है क्योंकि इसमें रक्तहानि एवं मानहानि का जोखिम नहीं है।

♦♦♦♦♦

6

आतंकवादः राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय के रूप मे

सृष्टि
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

आतंकवाद एक जटिल तथा परिवर्तनशील घटना है। आतंकवाद एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा समाज में भय तथा डर पैदा किया जाता है। आतंक का विधिवत प्रयोग आमतौर पर हिंसक व प्रपीडन का माध्यम होता है आतंकी कार्य के उद्देश्य आमतौर पर राजनीतिक होते हैं वे वैचारिक एवं धार्मिक रूप से न्यायोचित कराने का प्रयास करते हैं। अतः आतंकवाद एक वैश्विक परिघटना है यह राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा में चुनौती बन गया है।

21 वीं शताब्दी में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को अमेरिका पर प्रत्यक्ष प्रहार व विशेषकर 11 सितंबर 2001 को अपराजय हमले ने समस्त विश्व को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के एक ऐसे विषय जाल में फंसा दिया कि अब आतंकवाद का संकट कुछ सीमाओ या विश्व के कुछ देशों से ही बधा नहीं रह गया अपितु अब अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए विश्व के किसी भी कोने में पहुंच सकता है विश्व के विभिन्न भागों में आर्थिक व राजनीतिक वैश्वीकरण में शामिल पद्धतियों में तकनीकों के साथ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के संकट को आने वाले वर्षों में और भी प्रोत्साहन व व्यवहारिक गति मिलनी तय है। अतः वैश्वीकरण के युग में आतंकवादी गुटों के पक्ष में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के रूप में महान परिवर्तन हुए हैं जिसमें विभिन्न समाजों के राज्यों को आतंकवाद की समस्या का सामना करने के लिए एक वैश्विक रणनीति बनाने व संगठित प्रयासों के लिए मजबूर किया है।

वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं व परिणामों से जुड़े तीव्र प्रोधौगिक विकास ने न केवल अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद को उनकी ऐसी गतिविधियों के सफल संचालन में मदद की है जिससे वे अब समन्वित और सुनियोजित ढंग से अपने काम को अंजाम दे पाते हैं अपितु इसने आधुनिक तकनीक की उपलब्ध सुविध ाओं के प्रयोग से इसके सुरक्षा एजेंसियों की नजर से बच निकलने के रास्ते भी आसान बना दिए हैं। एक पृथक आधार पर व्यक्तिगत और एकल आतंकी हमले के युग के विपरीत वैश्वीकरण के युग में आतंकवाद ने सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा आधुनिक सुविधाओं के प्रयोग से गतिविधियों की विविधता और समन्वयन प्राप्त कर लिया है।

अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद की प्रतियोगी निवारण तथा उन्हें दंडित करने के बारे में अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौते हो चुके हैं, जो निम्न प्रकार से है।

 आतंकवाद के निवारण तथा उसे दंडित करने के लिए 1937 का कन्वेंशन– 1 नवंबर से 16 नवंबर, 1937 तक जिनेवा में आयोजित अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में दो कन्वेंशनो को स्वीकार किया। एक

कन्वेंशन आतंकवाद के निवारण और उसे दंडित करने के बारे में था। तथा दूसरा एक अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय की स्थापना के बारे में था। आतंकवाद का निवारण और उसे दंडित करने के बारे में कन्वेंशन में एक भूमिका तथा 29 धाराए थी भूमिका में इस बात पर बल दिया गया कि यह कन्वेंशन अंतरराष्ट्रीय चरित्र वाले आतंकवाद के निवारण तथा उसे दंडित करने के काम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लक्षित हैं।

 अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले और व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध तथा उससे बलवत छीना–झपटी का रूप धारण करने वाले आतंकवादी कृत्यों के निवारण और उन्हें दंडित करने के लिए 1971 का कन्वेंशन– अमेरिकी राज्यों के संगठन की महासभा ने 25 जनवरी से 2 फरवरी, 1971 तक वाशिंगटन में आयोजित अपने अधिवेशन में 6 अंतरराष्ट्रीय महत्व वाले और व्यक्तियों के विरुद्ध अपराध से छीना–झपटी का रूप धारण करने वाले आतंकवादी प्रतियोगी निवारण और उन्हें दंडित करने के लिए कन्वेंशन को स्वीकृति दी। इस कन्वेंशन में एक प्रस्तावना और 13 धाराएं हैं। प्रस्तावना इस बात पर बल देती है कि अमरीकी राज्यों के संगठन की महासभा ने अपने 30 जून 1970 के प्रस्ताव संख्या 4 में आतंकवादी क्रत्यो, विशेषतरू व्यक्तियों के अपहरण तथा इस अपराध के क्रम में उनसे बलपूर्वक छीना–झपटी की निंदा की है और ऐसे अपराधिक कृत्यो को "सामान्य अपराध गंभीर" घोषित किया है।

 आतंकवाद को रोकने के बारे में 1977 का यूरोपीय कन्वेंशन– यूरोपीय देशों के कानूनी सहयोग से आतंकवाद को रोकने के लिए यूरोपीय कन्वेंशन की रचना हुई।कन्वेंशन में 16 धाराएँ है और एक भूमिका है। जैसा कि भूमिका में बताया गया है, कन्वेंशन का उद्देश्य ऐसे प्रभावी उपाय करना था जिनसे यह निश्चित किया जा सके कि आतंकवादी कृत्यों के कर्ता मुकदमे तथा दंड से नहीं बच सकेंगे।

भारत एक लोकतांत्रिक और जिम्मेदार राष्ट्र है विश्व शांति हमारा ध्येय है लेकिन पड़ोसी देश पाकिस्तान हमारे खिलाफ आतंकवादी कार्यवाही करके हमारी संप्रभुता और स्वतंत्रता को लगातार अस्थिर करने की साजिश करता रहा है ऐसे में हमें अपनी सीमा की रक्षा करना फर्ज बनता है। बीते 30 वर्षों से पाकिस्तान की धरती से भारत के खिलाफ चलाए जा रहे छदम् युद्ध से भारत को काफी नुकसान हो चुका है। उरी में 2016 में आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था इस बात का संकेत था कि भारत ने एक जिम्मेदार देश की भांति अपनी रणनीति बदल ली है। अब वह जैश– ए– मोहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा, हिज्बुल मुजाहिदीन और उन जैसे अन्य आतंकी गुटों के जरिए पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे छदम् युद्ध से अपने नागरिकों की आक्रमक सुरक्षा नीति पर चलेगा। आतंकी संगठन पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की मदद से भारत में घुसपैठ जारी रखे हुए हैं। हाल में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर फिदायीन हमले, जिसे जैश– ए– मोहम्मद ने पाकिस्तान की सेना और आईएसआई की शह पर अंजाम दिया, में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए इस हमले से साबित होता है कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ छदम् युद्ध लड़ने को अपनी नीति का अंग बना रखा है।

26 फरवरी, 2019 को बारह मिराज लड़ाकू विमानों ने पूरी तरह से लक्ष्य केंद्रित होते हुए जैश–ए–

मोहम्मद के पाकिस्तान स्थित सबसे बड़े प्रशिक्षण शिविर को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के बहुत भीतर बालाकोट स्थित इस शिविर पर भारत के लड़ाकू विमानों ने असैन्य निशाना साधा। यह आतंकी ठिकाना नागरिक आबादी से दूर एक पहाड़ पर घने जंगलों के बीच बनाया गया था। भारतीय वायुसेना ने अपने अटैक में ध्यान रखा की नागरिक कतई निशाना न बनने पाए। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अटैक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं था न ही उसके लोगो और सैन्य प्रतिष्ठान के खिलाफ। केवल आतंकी ठिकानों पर था।

पाकिस्तान द्वारा चलाए जा रहे छदम् युद्ध के सामने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत को सीएनपी के प्रत्येक हिस्से का प्रयोग करना होगा। तात्पर्य यह कि भारत को बहूकोणिय तरीके– कूटनीतिक, राजनीतिक, सैन्य, सूचना एवं तकनीकी आक्रमकता –पाकिस्तान के खिलाफ अपनाने होंगे। मुख्य खिलाड़ी होने के नाते पाकिस्तानी सेना अपने देश में यह प्रभाव बनाए रखना चाहेगी कि भारतीय खतरे से बचाए रखने तथा कश्मीर के मुद्दे को गर्म रखने में वही सक्षम है। पाकिस्तान के लिए भारत को असामान्य विकल्प अपनाने आवश्यक है। जहां तक कूटनीतिक विकल्प की आक्रामकता का प्रश्न है तो विश्व समुदाय जानता है कि पाकिस्तान आतंक का केंद्र है।

भारत ने पाकिस्तान को "मोस्ट फेवर्ड नेशन" के दरजे से हटा दिया है वहां से आयातित वस्तुओं पर 200ः का शुल्क भी लगा दिया है अपितु अभी बहुत किया जाना बाकी है। हमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के समक्ष भी अपनी बात रखनी होगी ताकि भविष्य में पाकिस्तान को कर्ज देने में दिक्कत पेश आए जिससे कि उस पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तान में न करने पाए। अतरू आतंकवाद का आधारभूत ढांचा नष्ट करना, इसे मिलने वाला समर्थन समाप्त करना और आतंकियों तथा उनके समर्थकों को सजा देना बहुत आवश्यक है। देश को जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद और अन्य सभी मतभेदों को भुलाकर आतंक के खिलाफ अधिक दृढ़ता से सशक्त होना होगा।

♦♦♦♦♦

7

ड्रग तस्करी व नार्को–आतंकवाद

विजय प्रकाश सिंह
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

आतंकवाद क्या है? इसकी कोई एक परिभाषा नहीं है। आतंकवाद की परिभाषा हर सन्दर्भ में और इसके रूप पर निर्भर करती है. जहाँ एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति में आतंकवाद को क्रांति के एक मार्ग रूप में परिभाषित किया जाता है तो वहीँ 11 सितम्बर 2001 का विश्व व्यापार संगठन की इमारत पर हमला इसे धर्म का चोला पहनाता है। सरल भाषा में आतंकवाद हिंसा का एक गैर–कानूनी तरीका है जो लोगों को डराने के लिये आतंकवादियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। लोगों का समूह जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं व आतंकवाद को फैलाने में सहायता करते हैं उन्हें आतंकवादी कहा जाता है । गैर–राज्य कर्ताओं द्वारा किये गए राजनीतिक, वैचारिक या धार्मिक हिंसा को भी आतंकवाद की श्रेणी का ही समझा जाता है।

ये गैर–राज्य कर्ता या आतंकवादी समूह शक्तिशाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निहित हितों द्वारा प्रशिक्षित, प्रेरित और वित्तपोषित हैं, वे इन शक्तियों से घातक हथियार प्राप्त करते हैं. हालाँकि विश्व ने आतंकवाद के कई स्वरुप देखें हैं जिनमें राज्य प्रायोजित आतंकवाद, नागरिक अव्यवस्था व राजनैतिक आतंकवाद प्रमुख रूप से शामिल हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विश्व ने आतंकवाद के स्वरुप में परिवर्तन देखा है, जहाँ आतंकवाद एक राष्ट्र की सीमा पार कर दुसरे राष्ट्र को भी प्रभावित कर रहा है। इनमें मुख्य रूप से न्यूक्लियर आतंकवाद, जैवीय आतंकवाद, साइबर–आतंकवाद व नार्को–आतंकवाद शामिल हैं। इन सभी में से नार्को–आतंकवाद की समस्या विश्व के कई देशों में प्रासंगिक है, जिनमें अमेरिका व भारत जैसे देश शामिल हैं. लेकिन सबसे पहले हमें इसके इतिहास में जाना होगा.

नार्को–आतंकवाद, मादक पदार्थों के व्यापार व आतंकवाद के बीच का सम्बन्ध है। सरल भाषा में मादक पदार्थों के व्यापार से मिलने वाले धन का प्रयोग जब आतंकवाद के लिए किया जाता है तब इस पूरी प्रक्रिया को नार्को–आतंकवाद कहा जाता है. सबसे प्रथम इस शब्द का प्रयोग 1980 में लैटिन अमेरिका में हो रहे मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के संकट को दर्शाने के लिए पेरु के राष्ट्रपति बेलौंदे टेरी के द्वारा हुआ था तथा बाद में यह संकट पुरे संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैल गया। हालाँकि अमेरिकी सरकार मादक पदार्थों के इन तस्करियों पर काबू करने पाने में असफल रही और इसके बाद हम देख सकते हैं कि धीरे–धीरे इसका असर विश्व के दुसरे छोर पर भी दिखा।

इसका सबसे प्रथम उदाहरण स्वर्ण त्रिकोण या गोल्डन ट्रायंगल है जो तीन देशों से मिल कर बना है जो हैं म्यांमार, थाईलैंड व लाओस। जहाँ म्यांमार में अफीम की खेती की जाती है तथा यहाँ से इसे

थाईलैंड व लाओस के जरिये अन्य एशियाई देशों में इसकी अवैध रूप से तस्करी की जाती है. उदाहरणस्वरूप म्यांमार से आने वाले मादक पदर्थों की भारत के उत्तर–पूर्वी राज्यों में अवैध रूप से तस्करी की जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर मणिपुर में देखा गया है जहाँ की युवा जनसंख्या इससे सबसे ज्यादा ग्रसित है. ध्यान देने वाली बात यह है कि मादक पदार्थ के सेवन से इन युवाओं में एचआईवी/एड्स जैसी घातक बीमारियाँ फैल रहीं हैं क्योंकि कई युवा मादक पदार्थों का सेवन एक ही इंजेक्शन के द्वारा करते हैं जिसकी वजह से ऐसी बीमारियाँ एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति तक पहुँच जाती हैं. इस तरह देखा जा सकता है कि यह समस्या न केवल भारत की सीमा सुरक्षा पर सवाल उठाती है बल्कि इसकी आतंरिक सुरक्षा पर भी.

लेकिन सन् 1991 के बाद ड्रग तस्करी के मार्ग में परिवर्तन आया और इसका रूख दक्षिण–पश्चिम एशिया की ओर हो गया जहाँ इस मार्ग को स्वर्ण वर्धमान या गोल्डन क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है जो तीन देशों अर्थात् अफगानिस्तान, पाकिस्तान व ईरान से मिल कर बना है। जहाँ अफगानिस्तान व पाकिस्तान में अफीम आदि का उत्पादन होता है, वहीं ईरान में इसे तैयार कर बाकि अन्य देशों, जैसे– यूरोप व अमेरिका आदि, में बेचा जाता है।

नार्को–आतंकवाद की यह समस्या दक्षिण–पश्चिम एशिया में सबसे पहले तब शुरू हुई जब सोवियत बलों द्वारा अफगानिस्तान में घुसपैठ की गई. इस बाहरी घुसपैठ से लड़ने व अपने इस्लाम की रक्षा करने हेतु जिहादियों को हथियार मुहैय्या कराने के लिए पैसों का इंतजाम ड्रग तस्करी के द्वारा किया जाने लगा.

हालाँकि भारत भी नार्को–आतंकवाद के संकट से बच नहीं पाया है और पाकिस्तान का तो पहले से ही यह उद्देश्य रहा है कि वो किस तरह से भारत की सरकार को अस्थिर कर सके। चूँकि भारत के दो ऐसे राज्य, जम्मू व कश्मीर और पंजाब, जो पाकिस्तान से सटे हुए हैं जहाँ पर अक्सर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की जाती है वहां न केवल आतंकवादियों को वित्तीय सहायता इन मादक पदार्थों की तस्करी से प्रदान की जाती है बल्कि इन राज्यों के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में अलगाववादी दंगों को भड़काने हेतु अलगाववादी संगठनों को वित्तीय सहायता मुहैय्या करवाई जाती है.

सामान्य रूप में आतंकवाद और विशिष्ट रूप में नार्को–आतंकवाद न केवल भारत के लिए बल्कि पुरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और यह अब हर देश की सीमा में घुस कर उसके नागरीकों को प्रभावित कर रहा है. साथ ही साथ इस प्रक्रिया में न केवल मादक पदार्थों की तस्करी होती है बल्कि इसी दौरान देह व्यापार, बाल शोषण आदि जैसे अपराधों को भी अंजाम दिया जाता है. ऐसे में यह सवाल उठता है कि तमाम देशों की सरकारें क्यों अभी तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाई है. और क्यों पाकिस्तान जैसे देशों पर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की जा रही है, जहाँ से राज्य द्वारा नार्को–आतंकवाद को अन्य देशों में फैलाया जा रहा है. इन सवालों का जवाब मिलना और इस समस्या के लिए कई कठोर नीतियों का कार्यान्वयन अभी बाकि है.

♦♦♦♦♦

8

विश्व एवं आंतकवाद

मोहिनी
शोधार्थी, जयपुर दिल्ली विश्वविद्यालय

वर्तमान विश्व के समक्ष आतंकवाद प्रमुख चुनौती है, आंतकवाद से तात्पर्य है– किसी व्यक्ति, संस्था, समूह या देश द्वारा अपने आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक व विचारात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए लोगों में हिंसा फैलाकर भय या आंतक उत्पन्न करना। आतंकवादियों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु गैर सैनिकों को भी निशाना बनाया जाता है। आतंकवाद चरमपंथ व उग्रवाद से भिन्न है। चरमपंथ से तात्पर्य है – किसी व्यक्ति द्वारा कठोर तरीके से अपनी विचारधारा व नियमों का पालन करना व किसी दूसरे पर उन्हें थोपने का प्रयास करना। किन्तु चरमपंथियों द्वारा सामान्यतः हिंसा का सहारा नहीं लिया जाता, जबकि आतंकवाद का मुख्य लक्ष्य आम व्यक्ति ही होते हैं।

आतंकवाद के कारणों की यदि बात की जाए तो इसका सबसे प्रमुख कारण है– कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना है, कुछ स्वार्थी तत्व धर्म की अपने हितों के अनुकूल गलत व्याख्या करके धार्मिक कट्टरता व आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। इस के साथ–साथ आर्थिक सामाजिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, गलत विचारधारा का प्रचार प्रसार, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था के प्रति असंतोष की भावना, सभी को समुचित न्याय प्राप्त न हो पाना भी आतंकवाद के प्रमुख कारण हैं।

वर्तमान में आतंकवाद के बदलते आयाम सामने आ रहे हैं, जैसे– साइबर आतंकवाद, पर्यावरणीय आतंकवाद व भूमण्डलीकरण आयाम। जिससे आतंकवाद का क्षेत्र विस्तृत हुआ है। और यह सम्पूर्ण विश्व के लिए एक साझी समस्या बन गया है।, जो नकारात्मक रूप से विश्व को प्रभावित कर रहा है। वर्तमान में अलकायदा, आईएसआईएस जैसे अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का नेटवर्क विश्व स्तर पर फैला हुआ है।

भारत सीमा पार आतंकवाद से हमेशा से प्रभावित रहा है और इसे खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर एक पहलकारी भूमिका अदा कर रहा है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारत आतंकवाद के दर्द को झेल रहा है। भारत में आतंकवाद मुख्यतः पडोसी देश पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित है। कश्मीर, नागालैंड, पंजाब, असम व बिहार राज्य तथा देश की राजधानी दिल्ली विशेष रूप से आतंकवाद से प्रभावित है।

भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अलकायदा, लश्कर–ए–तैयबा, बब्बर खालसा, जैश–ए–मोहम्मद, उल्फा समेत 35 से ज्यादा आतंकवादी संगठनों को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाल रखा है। मुंबई में 26ध्11का आतंकवादी हमला हो या फिर दिल्ली का हमला या उरी और पुलवामा जैसे

आतंकवादी हमले भारत के लिए आतंकवाद एक बड़ी समस्या बना हुआ है।

ये आतंकवादी संगठन अपने स्वार्थ हेतु एक विचारधारा विशेष को ढाल बनाते हैं। और तुष्टिकरण की नीति अपना कर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इन संगठनों द्वारा राष्ट्रीय एकता व सुरक्षा को खतरा पहुंचाया जाता है। इन संगठनों को विदेशी तत्वों व संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता व हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई व माओवादियों द्वारा आतंकवादी संगठनों को आर्थिक सहायता व हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस के अलावा कुछ राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए देश विरोधी बयान, साम्प्रदायिक तत्वों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। भारत में कुछ क्षेत्रों में पाए जाने वाले आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन, विकास के अभाव, बढ़ती बेरोजगारी के कारण भी आतंकवाद को बढ़ावा मिला है।

2001 में हुआ संसद भवन पर हमला, 2006 का मुम्बई बम विस्फोट, 2008 मे ताज होटल में हुआ आतंकवादी हमला जिसमें एक आतंकवादी कसाब को जिंदा पकड़ा गया और 2012 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई, अमरनाथ यात्रा पर हमला, उरी हमला व हाल में हुआ पुलवामा हमला बड़े आतंकवादी हमले हैं, जो भारत की सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते आए हैं। प्रारंभ में भारत द्वारा आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए बातचीत का प्रयास किया गया। भारत द्वारा बार–बार वार्ता के माध्यम से समस्या को सुलझाने का प्रयास किया गया किन्तु इसका अपेक्षित समाधान प्राप्त नहीं हुआ। वर्तमान में 2014 से भारत के आतंकवाद के समाधान करने के तरीके में बदलाव आया है।

भारत का द्रष्टिकोण बदला है। अब भारत का सीधा मानना है कि बम, बंदूक व बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी जाएगी। मणिपुर में हुए हमले के बाद भारत द्वारा सख्त कदम उठाया गया। उरी हमले के बाद भारत द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा हमले के बाद की गई एयर स्ट्राइक भारत के बदलते हुए रुख को स्पष्ट करता है।

चूंकि आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है, तो इसके विरोध में साझी कार्यवाही की जानी चाहिए, आंतकवाद के विरोध में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनका वैश्विक स्तर पर बहिष्कार हो वो सभी राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र के मंच पर उसके विरुद्ध एक साथ आएं। इसके साथ साथ विकास पर भी बल दिया जाए। शिक्षा में नैतिकता को बल दिया जाना चाहिए। आतंकवाद के सभी रूपों का विरोध होना चाहिए।आतंकवाद में अच्छा या बुरा जैसा कोई विभाजन नहीं होता। सभी प्रकार का आतंकवाद मानवता के विरुद्ध है। असहिष्णुता व आतंकवाद फैलाने वाले व्यक्ति, संस्था व संगठनों के विरोध में एकजुट होकर कार्रवाई की जानी चाहिए किसी भी देश की सुरक्षा व एकता प्राथमिक राष्ट्रीय हित है, इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।

♦♦♦♦♦

9

आंतकवादः बदलता स्वरूप एवं चुनौतियॉ

विद्यासागर शर्मा
शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पूरा विश्व जब भूमंडलीकरण के कारण विकास के नए आयामों को छू रहा है और मानवीय अस्तित्व भी मजबूती से इस विकास प्रक्रिया में कदमताल कर रहा है लेकिन इस गतिशील प्रक्रिया को लगातार जिस चीज से चुनौती मिल रही है वो है "आतंकवाद"। आतंकवाद समकालीन विश्व की सबसे ज्वलंत समस्या है जिसने विश्व के अधिकांश राष्ट्र चाहे वो विकसित हो या विकासशील अपनी चपेट में ले रखा है। आतंकवाद ने न सिर्फ वैश्विक सुरक्षा को चुनौती दिया है बल्कि इसने मानवीय अस्तित्व को भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आतंकवाद को अगर हम परिभाषित करे तो सामान्य अर्थों में इसका तात्पर्य एक ऐसी विचारधारा से है जो अपने हितों को पूरा करने के लिए हिंसा और भय का सहारा लेती है, चाहे वो हिंसा धार्मिक कट्टरतावाद के रूप में हो या नस्लीय हिंसा के रूप में हो।

आतंकवाद की हाल की घटनाओं ने भारत से जैसे शांतिप्रिय राष्ट्र की सुरक्षा को एक बार पुनः चर्चा में लाकर रख दिया है। मसला चाहे लन्दन मेट्रो में हुए आतंकी हमले का हो या रोहिंग्या शरणार्थियों को भारत में प्रवेश के कारण उठा सुरक्षा का सवाल हो। भारत अपने अतीत के कारण आतंकवाद का भुक्तभोगी रहा है। सीमापार आतंकवादी सक्रियता एवं पाकिस्तान पोषित आतंकवाद ने भारत के लिए गंभीर समस्याएं पैदा की हैं। भारतीय सीमा के अंदर कई बार आतंकी हमले हुए हैं चाहे वो २६/११ का हमला हो या मुंबई सीरियल ब्लास्ट और ऐसे कई हमले हुये हैं जिसने भारतीय जन समुदाय को काफी क्षति पहुँचाया है और ये बात सर्वविदित है कि इन हमलों के पीछे पाकिस्तान पोषित संगठनों का हाथ रहा है।

भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रियों मंचों से कड़ी चुनौतियाँ पेश की हैं और हाल हीं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से आतंकवाद के खिलाफ एक नई मुहीम की शुरुआत की है और उन्होंने विश्व समुदाय से अनुरोध किया है कि वो आतंकववाद के खिलाफ एक साथ आएं और हाल हीं में अमेरिकी ट्रम्प सरकार ने अपनी अफगान नीति की घोषणा के दौरान भारत के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ मुहीम शुरू करने की बात की है।

आतंकवाद के बदलते स्वरुप के कारण इसकी जटिलताओं ने भी कई स्वरुप ग्रहण किये हैं । संचार तकनीक और सोशल मीडिया के तीव्र विकास ने साइबर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। आतंकी संगठनों ने इन तकनीकी सेवाओं को अपने हथियारों के रूप में अपना लिया है। साइबर आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत ने भी कई कड़े कदम उठाये हैं जिसमे आधार आधारित पहचान पत्र को

तकनीकी सेवाओं के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि संदिग्ध व्यक्ति की आसानी से पहचान हो सके। भारत सरकार कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ मिल कर साइबर हमलों को रोकने के लिए काम कर रही है।

आतंकवाद जैसी समस्या के कारण न सिर्फ राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा पहुँचता है बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था भी कमजोर पड़ने लगती है क्योंकि अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है निवेश और खासकर वैश्विक निवेशक निवेश करते वक्त एक सुरक्षित वातावरण की उम्मीद करते हैं और ऐसी परिस्थतियों में जब राष्ट्र की सुरक्षा सवालों में हो तो निवेशक भी दूर रहते हैं और इसका परिणाम अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ता है। आतंकवाद के गहराते जड़ों को कमजोर करने के लिए वर्तमान मोदी सरकार ने विमुद्रीकरण जैसे कठोर कदम उठायें हैं ताकि आतंकवादी संगठनों को मिल रहे अवैध पैसों पर नियंत्रण लगाया जा सके ।

वर्तमान भारत बाह्य आतंकवाद के साथ – साथ आंतरिक आतंकवाद के साथ भी संघर्ष कर रहा है जैसे– नक्सल समस्या और विभिन उग्रवादी संगठन जैसे उल्फा आदि की सक्रियता। इन संगठनों ने आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिशें की है लेकिन सरकार के दृढ संकल्प के कारण इस संगठनों पर लगाम लगाया जा सका है । भारतीय गुप्तचर एजेंसियां जैसे रॉ और आईबी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर रहीं हैं और इन संगठनों के कारण हीं हम भारत को आतंकवाद से मुक्त बनाने की तरफ निरंतर अग्रसर हो रहें हैं।

आज पुरे विश्व को आतंकवाद मुक्त बनाना मानवीय सभ्यता के लिए नितांत आवश्यक है और भारत इसमें अग्रणी भूमिका अदा करने के लिए सदैव तत्पर रहा है। आज पुरे मानव समुदाय को जरुरत है कि वो अपने साथ और अन्य समुदायों के साथ साहचर्य बनाकर रखे ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा समाज और वातावरण दे सके जिसमे भय का कोई स्थान न हो। हर व्यक्ति को अपने विकास का पूरा अवसर मिल सके और साथ हीं हम वसुधैव कुटुंबकम के सपने को साकार कर सके। भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी एकता और अखंडता को तभी कायम रख पायेगा जब हम सब एक संवेदनशील प्राणी की तरह अपने पर्यावरण और मानवीय संबंधों को मजबूत बनाकर रखेंगे अन्यथा अलगाववाद की भावना पनपने लगेगी और परिणामतः आतंकवाद जैसी अमानवीय त्रासदी पूरी सभ्यता को नष्ट कर देगी ।

♦♦♦♦♦

डी.सी.आर.सी.

विकासशील राज्य शोध केन्द्र

अकादमिक अनुसंधान केन्द्र भवन

गुरू तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली–110007